Answer Key

Class -12

Political Science

1.मुस्लिम लीग

2.आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम)

(Maintenance of Internal Security Act)

3. काठमांडू नेपाल में

4. लाल बहादुर शास्त्री ने

5 .B इंदिरा गांधी

6 .D वीपी सिंह

7. D जयप्रकाश नारायण

8. B अप्रैल 1980

9. Aभारत और बांग्लादेश

10.Aभारत और श्रीलंका

11.A1974 में

12.Dउपर्युक्त सभी

13.Dउपर्युक्त सभी

14. A1997

15.Aभारत-पाकिस्तान

16.Cभारतीय जन संघ

17.Dकिसान

18.Bशांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पांच सिद्धांत

19.Aआर्थिक मॉडल

20. अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों व लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र

21.अमेरिका

22. 5 and 10

23. क

24. क

25.भारतीय जनसंघ (BJS) की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी । यह एक दक्षिणपंथी, राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था, जिसे भारतीय जनता पार्टी (BJP) का वैचारिक अग्रदूत माना जाता है ।इस दल से जुड़े मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:उद्देश्य: इसका मुख्य लक्ष्य 'एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र' के विचार को

बढ़ावा देना, अखंड भारत का निर्माण, और भारतीय संस्कृति व परंपराओं के आधार पर देश का आधुनिकीकरण करना था ।

Or

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके ठीक बाद एक 'छाता संगठन' (Umbrella Organisation) इसलिए कहा गया, क्योंकि इसने एक ही मंच के नीचे विभिन्न विचारधाराओं, धर्मों, जातियों और वर्गों के लोगों को एकजुट किया था ।

26. विदेश नीति हमेशा घरेलू आवश्यकताओं (जैसे आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा) और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों (जैसे शीतयुद्ध, वैश्विक महाशक्तियों के समीकरण) के बीच संतुलन बनाने का परिणाम होती है ।

1960 के दशक में भारत की विदेश नीति इसका सटीक उदाहरण है:

अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति: 1962 के भारत-चीन युद्ध और 1965 के भारत-पाक युद्ध के कारण भारत की सुरक्षा को बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ ।

घरेलू आवश्यकता: उस समय देश में भयानक खाद्य संकट (अकाल) था और रक्षा आधुनिकीकरण के लिए भारी आर्थिक संसाधनों की कमी थी ।

or

गुटनिरपेक्षता (Non-alignment) का अर्थ किसी भी अंतरराष्ट्रीय शक्ति गुट (विशेषकर शीत युद्ध के दौरान अमेरिका या सोवियत संघ) में शामिल न होकर, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना और हर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे का गुण-दोष के आधार पर निष्पक्ष मूल्यांकन करना है ।इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा अंतरराष्ट्रीय मामलों में किसी महाशक्ति के दबाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है ।

27. वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार मुख्य रूप से बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में ऐतिहासिक सैन्य विजय, 'गरीबी हटाओ' के लोकलुभावन नारे, और मजबूत नेतृत्व क्षमता के कारण अत्यधिक लोकप्रिय हुई थी ।

28. जनता पार्टी सरकार ने मई 1977 में शाह आयोग (Shah Commission) की नियुक्ति आपातकाल (1975-1977) के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा की गई ज्यादतियों, सत्ता के दुरुपयोग और असंवैधानिक फैसलों की जांच करने के लिए की थी ।

29.सोवियत संघ (USSR) के विघटन (1991) का भारत पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ा । इससे भारत को अपनी विदेश नीति, रक्षा और अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव करने पड़े ।Or

सोवियत प्रणाली (Soviet System) की दो प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

राज्य का स्वामित्व: इसमें उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण था । अर्थव्यवस्था को एक केंद्रीय योजना के तहत चलाया जाता था, जिसमें निजी संपत्ति की कोई जगह नहीं थी ।

कल्याणकारी राज्य और न्यूनतम जीवन स्तर: सोवियत प्रणाली में नागरिकों को बुनियादी जीवन स्तर (जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, और सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थ) की गारंटी राज्य द्वारा दी जाती थी ।

30. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) के मुख्य दो कार्य निम्नलिखित हैं:अंतरराष्ट्रीय शांति और

सुरक्षा बनाए रखना: विश्व में संघर्षों को रोकना, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालना और आवश्यकता पड़ने पर शांति सैनिकों (Peacekeeping forces) को तैनात करना ।

31.दक्षिण एशिया में बाहरी शक्तियाँ (जैसे अमेरिका, चीन, रूस, और यूरोपीय संघ) राजनीतिक, आर्थिक, और सैन्य संबंधों के माध्यम से क्षेत्रीय राजनीति को गहराई से प्रभावित करती हैं। वे द्विपक्षीय व्यापार, रणनीतिक साझेदारी, और हथियारों की आपूर्ति द्वारा क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और देशों के आपसी संबंधों को दिशा देती हैं।

32. विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव (वैश्वीकरण) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया भर के देश, समाज, अर्थव्यवस्थाएं और संस्कृतियाँ आपस में जुड़ रही हैं और उनके बीच परस्पर निर्भरता बढ़ रही है। इसके कारण सीमाओं के आर-पार विचारों, वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का तीव्र प्रवाह संभव हुआ है ।

33.आजादी के समय विकास के सवाल पर मुख्य रूप से दो मतभेद थे: पूंजीवाद बनाम समाजवाद (निजी क्षेत्र बनाम सरकार) और औद्योगीकरण बनाम कृषि।

हां, इन मतभेदों को सुलझा लिया गया। भारतीय नेतृत्व ने दोनों के बीच का रास्ता निकालते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया।

Or

विकास (Development) के तीन मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:जीवन स्तर में सुधार: लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं (जैसे: भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, और स्वास्थ्य) को पूरा करना और उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना।समानता और सामाजिक न्याय: समाज के सभी वर्गों के बीच आय की असमानता को कम करना और जाति, लिंग या धर्म के भेदभाव के बिना सभी को समान अवसर प्रदान करना।आत्मनिर्भरता और आर्थिक संवृद्धि

34. आपातकाल (1975-1977) के बाद के दौर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का उदय और विकास भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 1980 में अपनी स्थापना से लेकर केंद्र में एक विशाल बहुमत वाली सरकार बनाने तक, पार्टी का सफर वैचारिक प्रतिबद्धता और रणनीतिक विस्तार का परिणाम रहा है।भाजपा के विकास-क्रम को निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है:

1. जनता पार्टी का गठन और जनसंघ का विलय (1977)आपातकाल के विरोध में सभी गैर-कांग्रेसी दल एकजुट हुए और जनता पार्टी बनी। इसमें 'भारतीय जनसंघ' (भाजपा का पूर्ववर्ती दल) भी शामिल था। 1977 के चुनावों में जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और केंद्र में पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। ।वर्तमान में केंद्र में 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ।

35. क्षेत्रीय संगठनों (Regional Organizations) के निर्माण के पीछे मुख्य रूप से भौगोलिक निकटता, साझा हित और पारस्परिक सहयोग की भावना होती है। क्षेत्रीय संगठनों के गठन के तीन प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देना: सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार को आसान बनाना ।

शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना:

क्षेत्रीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना और सदस्य देशों की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए एक सामूहिक सुरक्षा तंत्र का निर्माण करना। सांस्कृतिक और सामाजिक विकास ।

Or

इसके तीन मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

एकजुट और शांतिपूर्ण क्षेत्र: दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच शांति, अच्छे पड़ोसी संबंधों और साझा जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना। पूरे क्षेत्र को परमाणु हथियारों से मुक्त (Nuclear-Weapon-Free Zone) बनाए रखना।
साझा आर्थिक क्षेत्र: एक स्थिर, समृद्ध और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी आसियान आर्थिक क्षेत्र का निर्माण करना, जहाँ वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और कुशल श्रम का स्वतंत्र प्रवाह हो।
जीवंत और देखभाल करने वाला समाज ।
36. तीसरी दुनिया (विकासशील) और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में सबसे बड़ा अंतर उनकी आर्थिक स्थिति, संस्थागत मजबूती और बाहरी हस्तक्षेप का है इसे निम्न प्रमुख बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है:
1. बुनियादी और आंतरिक खतरेतीसरी दुनिया के देश: यहाँ की जनता के सामने मुख्य खतरे गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, और संक्रामक बीमारियों से जुड़े हैं। उन्हें पीने का साफ पानी, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ता है ।
विकसित देश: इन देशों में बुनियादी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। यहाँ की जनता के सामने मुख्य खतरे उच्च जीवन-शैली के कारण होने वाली आधुनिक बीमारियों (जैसे लाइफस्टाइल डिजीज), मानसिक तनाव, और अकेलेपन (जैसे सामाजिक अलगाव) से जुड़े हैं।
2. बाहरी खतरे और सुरक्षातीसरी दुनिया के देश: इन देशों को पड़ोसी देशों से सैन्य संघर्ष के अलावा महाशक्तियों के सैन्य, आर्थिक और वैचारिक हस्तक्षेप का खतरा रहता है। कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण इन्हें अक्सर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और अमीर देशों की शर्तों व दबावों का सामना करना पड़ता है। विकसित देश: प्रथम दुनिया के इन देशों के सामने प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमण का खतरा लगभग नगण्य होता है। इनके खतरे अधिक वैश्विक और रणनीतिक होते हैं, जैसे— अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर हमले, या वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रभाव ।

37.1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन (रियो सम्मेलन) के तीन प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं :
एजेंडा 21 (Agenda 21): सतत विकास (Sustainable Development) को प्राप्त करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की गई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और गरीबी मिटाने के लिए वैश्विक सहयोग के सिद्धांत शामिल थे ।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC): ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक संधि तैयार की गई , जिसके परिणामस्वरूप बाद में 'क्योटो प्रोटोकॉल' और 'पेरिस समझौता' जैसे ऐतिहासिक समझौते हुए ।
जैव विविधता पर कन्वेंशन ।
Or
विश्व की साझी विरासत (Global Heritage/Commons) का अर्थ उन प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संसाधनों से है जिन पर किसी एक व्यक्ति, समूह या देश का अधिकार नहीं होता है। इन पर पूरी मानव जाति का साझा अधिकार होता है और इनका संरक्षण संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है।साझी विरासत के प्रमुख उदाहरण-
पृथ्वी का वायुमंडल
समुद्री सतह व महासागर

बाहरी अंतरिक्ष

38.राष्ट्र निर्माण से तात्पर्य एक ऐसी सतत और समन्वित प्रक्रिया से है, जिसके माध्यम से किसी देश के विविध और विभाजित समाज को एक मजबूत, एकजुट और समृद्ध राष्ट्र में बदला जाता है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के जरिए राष्ट्रीय स्थिरता और एकता स्थापित की जाती है ।

राष्ट्र निर्माण के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं:राष्ट्रीय पहचान और एकता (National Identity): नागरिकों में एक साझा पहचान की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। इससे लोग क्षेत्रीय, भाषाई और धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठकर 'हम एक राष्ट्र हैं' की भावना से जुड़ते हैं । संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्य: एक राष्ट्र का निर्माण संविधान और कानून के शासन पर आधारित होता है। समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व जैसे मूल्य सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांधते हैं। मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाएं: न्यायपालिका, चुनाव आयोग और संसद जैसी स्वतंत्र संस्थाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाती हैं और राष्ट्र की स्थिरता सुनिश्चित करती है ।आर्थिक विकास और समानता ।

Or

सदियों पुरानी साझा विरासत, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों और एक मजबूत संवैधानिक ढांचे के सामूहिक विश्वास ने भारत को एक जीवंत राष्ट्र बनाया है ।भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाली प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:साझा इतिहास और विरासत: सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक, भारत का एक निरंतर ऐतिहासिक प्रवाह रहा है। हज़ारों वर्षों से चली आ रही सांस्कृतिक निरंतरता और साझा पूर्वजों की स्मृतियां भारतीयों को एक सूत्र में बांधती हैं ।भौगोलिक एकता: उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर जैसी प्राकृतिक सीमाएं एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान बनाती हैं, जो इस भूमि को एक अखंड इकाई का स्वरूप देती हैं ।विविधता में एकता ।

39. भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करते हुए विश्व शांति, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।

यह गुटनिरपेक्षता, पंचशील और रणनीतिक स्वायत्तता के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जो इसे स्वतंत्र और वैश्विक मंचों पर प्रभावशाली बनाते हैं। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment): शीत युद्ध के दौरान भारत ने किसी भी सैन्य गुट (अमेरिका या सोवियत संघ) में शामिल न होने की नीति अपनाई। आज भी भारत 'बहु-गुटीय' (Multi-alignment) दृष्टिकोण अपनाकर सभी प्रमुख शक्तियों के साथ राष्ट्रीय हित के आधार पर स्वतंत्र संबंध बनाए रखता है ।पंचशील के सिद्धांत (Panchsheel Principles),

साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध:

एक लंबा औपनिवेशिक इतिहास होने के कारण, भारत हमेशा विश्व स्तर पर साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद (जैसे दक्षिण अफ्रीका में) का कड़ा विरोधी रहा है ।

शांतिपूर्ण समाधान और संयुक्त राष्ट्र में विश्वास:

भारत अंतर राष्ट्रीय विवादों को युद्ध के बजाय बातचीत और शांतिपूर्ण माध्यमों से सुलझाने में विश्वास रखता है ।

यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता दिखाता है ।

रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy):

भारत किसी भी रक्षा या सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि अपनी नीतियों और निर्णयों में पूर्ण स्वतंत्रता बनाए रखता है ।आर्थिक और सांस्कृतिक कूटनीति ।

Or

भारत और पाकिस्तान के संबंध मुख्य रूप से 1947 में हुए विभाजन के बाद से ही विवादों और तनावों से घिरे रहे हैं। इन संबंधों की कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:मुख्य विवाद: दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण कश्मीर विवाद और सीमा पार आतंकवाद है।

प्रमुख युद्ध: दोनों देशों के बीच अब तक चार प्रमुख युद्ध (1947, 1965, 1971, और 1999) हो चुके हैं ।व्यापार और कूटनीति: वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध लगभग न के बराबर हैं।

2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से कूटनीतिक संबंधों में भारी गिरावट आई है।

शांति के प्रयास: तनाव के बावजूद, समय-समय पर दोनों देशों ने बातचीत और शांति समझौतों (जैसे- शिमला समझौता, आगरा शिखर सम्मेलन) के जरिए मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की है।

40. पंजाब समझौता (राजीव-लोंगोवाल समझौता) 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य पंजाब में शांति बहाल करना था।

इसके प्रावधानों में चंडीगढ़ का पंजाब को स्थानांतरण, क्षेत्रों की अदला-बदली और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद शामिल थे ।पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान

समझौते के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे:

चंडीगढ़ का स्थानांतरण: चंडीगढ़ को पंजाब को सौंप दिया जाना था।

क्षेत्रीय विवाद: पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवादों को सुलझाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाना था और हिंदी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा को सौंपा जाना था।

नदी जल बंटवारा: पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी-ब्यास नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर हुए विवाद के समाधान के लिए एक नया न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) गठित किया जाना था।

केंद्र-राज्य संबंध: केंद्र सरकार राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के मुद्दे पर विचार करेगी, जिसके लिए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को 'सरकारी आयोग' के पास भेजा गया।

न्याय और मुआवजा: 1984 के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाना था ।

Or

भारत में क्षेत्रवाद (Regionalism) के समाधान के लिए संतुलित आर्थिक विकास, सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism), और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना आवश्यक है। यह राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका है ।क्षेत्रवाद की समस्या से निपटने हेतु कुछ प्रमुख और व्यावहारिक सुझाव निम्नलिखित हैं:

समान और संतुलित आर्थिक विकास: पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों में विशेष आर्थिक पैकेज, औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास (जैसे- सड़कों, बिजली, पानी) पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि राज्यों के बीच आर्थिक असंतुलन समाप्त हो सके।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान और शिक्षा: 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना चाहिए।

स्कूली पाठचक्रम में विविधता और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को शामिल करने से भाषाई और सांस्कृतिक मतभेद दूर होते हैं ।अंतर-राज्य परिषद का प्रभावी उपयोग: राज्यों के बीच जल बंटवारे, सीमा विवाद और संसाधनों के आवंटन जैसे मुद्दों को बातचीत और आम सहमति से सुलझाने के लिए अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) की नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए ।
राजनीतिक इच्छाशक्ति: क्षेत्रीय दलों और नेताओं को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भाषा या क्षेत्र के नाम पर अलगाववादी भावनाओं को भड़काने से बचना चाहिए ।
वित्तीय स्वायत्तता और विकेंद्रीकरण:

41. एक भारतीय नागरिक के रूप में, मैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन निम्नलिखित मजबूत तर्कों, जैसे- दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, विशाल जनसंख्या, और वैश्विक शांति में अद्वितीय योगदान के आधार पर करूँगा । यह प्रस्ताव समकालीन भू-राजनीति की सच्चाई है, जो सुरक्षा परिषद को अधिक न्यायसंगत और प्रभावी बनाएगा ।भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में औचित्य और तर्क:लोकतांत्रिक मूल्य और विविधता: भारत विश्व का सबसे बड़ा जीवंत लोकतंत्र है ।
संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठन में आधी से अधिक आबादी और विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, भारत को स्थायी सीट मिलना अनिवार्य है ।
वैश्विक शांति में ऐतिहासिक योगदान: भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों (Peacekeeping Missions) में सबसे अधिक सैनिक भेजने वाला प्रमुख देश रहा है ।
भारत ने हमेशा बातचीत और कूटनीति के जरिए वैश्विक विवादों को सुलझाने का समर्थन किया है ।
आर्थिक और रणनीतिक कद: भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है ।
इसके अलावा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है ।
विकासशील देशों (Global South) का प्रतिनिधित्व: वर्तमान सुरक्षा परिषद का ढांचा द्वितीय विश्वयुद्ध के समय की परिस्थितियों पर आधारित है, जिसमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे बड़े महाद्वीपों का कोई स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं है । भारत की सदस्यता इस असंतुलन को दूर करेगी ।
जिम्मेदार परमाणु शक्ति: भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है ।
Or
संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) के छह प्रमुख अंग हैं जो वैश्विक शांति, सुरक्षा और मानवाधिकारों के लिए मिलकर काम करते हैं - इनका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:
1. महासभा (General Assembly):
यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार-विमर्श, नीति-निर्माण और प्रतिनिधि अंग है । इसमें सभी 193 सदस्य देश शामिल हैं । यहाँ प्रत्येक देश को एक वोट का अधिकार प्राप्त है । यह बजट पारित करने, नए सदस्यों को शामिल करने और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर प्रस्ताव पारित करती है ।
2. सुरक्षा परिषद (Security Council):

वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी इसी अंग की है। इसके 15 सदस्य होते हैं— 5 स्थायी सदस्य (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन) और 10 अस्थायी सदस्य जिन्हें दो वर्ष के लिए चुना जाता है। इसके स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर (Veto Power) होती है।

3. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice - ICJ):

हेग (नीदरलैंड) में स्थित यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। यह राज्यों (देशों) द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों का निपटारा करता है और कानूनी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के अंगों को सलाह देता है।

4. आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC):

यह अंग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर चर्चा और नीति-निर्माण का केंद्रीय मंच है। यह मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विशिष्ट एजेंसियों का समन्वय करता है।

5. सचिवालय (Secretariat):

यह संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है जो संगठन के दैनिक कार्य करता है। इसके प्रमुख महासचिव होते हैं जिनकी नियुक्ति महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है।

6. न्यास परिषद

42. वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है:

आर्थिक विकास: 1991 के उदारीकरण के बाद एफडीआई (FDI) और निर्यात में भारी उछाल आया है, जिससे देश में धन और आधुनिक उद्योगों का विस्तार हुआ है।रोज़गार के अवसर: आईटी (IT), ऑटोमोबाइल और संचार क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए रोज़गार के नए मार्ग खुले हैं।संस्कृति और रहन-सहन: खान-पान, पहनावे और दैनिक जीवन में पश्चिमी और वैश्विक संस्कृतियों का गहरा प्रभाव पड़ा है।

भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है:

आईटी और सेवाएं: इंफोसिस, टीसीएस जैसी भारतीय कंपनियों ने वैश्विक तकनीकी बाज़ार में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।वैश्विक बाज़ार और श्रम: भारत अपने विशाल उपभोक्ता बाज़ार और कुशल पेशेवर (डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक) देकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को संचालित कर रहा है।सांस्कृतिक प्रभाव: भारत का योग, आध्यात्मिकता, खान-पान (मसाले) और सिनेमा (बॉलीवुड) पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहे हैं।

Or

वैश्वीकरण (Globalisation) से तात्पर्य विश्व अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और समाजों के अंतर्संबंध से है।

सकारात्मक पक्ष:

आर्थिक विकास: विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से नए रोजगार और बेहतर जीवन स्तर का निर्माण होता है।

सस्ती वस्तुएं: वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण उपभोक्ताओं को कम दाम में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलते हैं।

तकनीक का प्रसार: त्वरित तकनीकी विकास और ज्ञान का आदान-प्रदान सुगम होता है।

नकारात्मक पक्ष:

असमानता में वृद्धि: इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी हो सकती है।

स्थानीय उद्योगों को खतरा: बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आड़ में छोटे और स्थानीय व्यापार प्रभावित होते हैं।

संस्कृति का क्षरण: स्थानीय पहचान कम होती है और पश्चिमीकरण को अत्यधिक बढ़ावा मिलता है।